

प्रेषक,

डी0एस0 गब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 26 अगस्त, 2015

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में नगर पालिका परिषद, नरेन्द्रनगर को अवस्थापना विकास निधि से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नरेन्द्रनगर के पत्रांक-332/अवस्थापना/2014-15, दि0-28.08.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर पालिका परिषद, नरेन्द्रनगर (जनपद टिहरी) के क्षेत्रान्तर्गत नरेन्द्रनगर सुमन पार्क के समीप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, टाउनहॉल, श्रीदेव सुमन पार्क एवं कार्यालय भवन निर्माण कार्य हेतु शासन को उपलब्ध कराये गए आगणन की टी0ए0सी0 वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत लागत ₹ 489.62 लाख (₹ 460.75 लाख निर्माण कार्यों हेतु एवं ₹ 28.87 लाख अधिप्राप्ति नियमावली के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों हेतु) की प्रशासनिक स्वीकृति के साथ-साथ ₹ 300.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹ 150.00 लाख (₹ एक करोड़ पचास लाख मात्र) निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (i) उक्तानुसार योजना लागत ₹ 489.62 लाख के सापेक्ष ₹ 300.00 लाख की धनराशि शासन द्वारा नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के विकास मद से स्वीकृत की जाएगी तथा शेष ₹ 189.62 लाख की व्यवस्था नगर पालिका परिषद, नरेन्द्रनगर द्वारा योजनान्तर्गत अर्जित होने वाली धनराशि तथा निकाय स्तर पर अवशेष राज्य वित्त आयोग की धनराशि से की जायेगी।
- (ii) चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि ₹ 150.00 लाख (₹ एक करोड़ पचास लाख मात्र) आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर पालिका परिषद, नरेन्द्रनगर को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
- (iii) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
- (iv) कार्यों को प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा तथा इस लागत में कोई वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
- (v) निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।
- (vi) स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।
- (vii) सभी निर्माण कार्य समय-समय पर गुणवत्ता एवं मानको के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे।

कमश/2

- (viii) कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
- (ix) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु नगर निकाय/कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।
- (x) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।
- (xi) निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।
- (xii) मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।
- (xiii) उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से करा लिया गया है, तो उक्त स्वीकृत कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।
- (xiv) नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले **Construction Agreement** में एक वर्ष का **Defect Liability Period** तथा 3 वर्ष तक **अनुक्षण** की शर्त भी रखी जायेगी।
- (xv) धनराशि का दिनांक 31-3-2016 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्य का वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

2- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान सं०-13 के लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास- आयोजनागत-191-स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-03-नगरों का समेकित विकास-05-“नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास”-‘20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता’ की मद के नामे ₹ 118.50 लाख, अनुदान सं०-30 के लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास- आयोजनागत-191-स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-03-नगरों का समेकित विकास-05-“नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास-42-अन्य व्यय की मद के नामे ₹ 27.00 लाख तथा अनुदान सं०-31 के लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास- आयोजनागत-191-स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-03-नगरों का समेकित विकास-05-“नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास”-‘20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता’ की मद के नामे ₹ 4.50 लाख डाला जाएगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 446/XXVII(2)/2015, दिनांक 25.08.2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-अलॉटमेंट आई०डी सं०- (1) S1508130162
(2) S1508300163
(3) S1508310164

भवदीय,

(डी०एस० गर्ब्याल)
सचिव।

कमरा./3

सं०-1059 (1)/IV(2)-श0वि0-45(सा0)/2012, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा० शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23-लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी।
6. जिलाधिकारी, टिहरी।
7. वित्त अनुभाग-2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी०ओ० में इसे शामिल करें।
9. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नरेन्द्रनगर।
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
संयुक्त सचिव।